विचार-प्रवाह

देहरादून, शनिवार, 6 नवंबर 2021

पेज थ्री

www.page3news.in

रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का कानून

भारत के टैक्स डिपार्टमेंट ने इस सौदे पर ब्रिटिश कंपनी से 200 करोड़ का टैक्स मांगा। वोडाफोन ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी और केस जीत गई। इसके बाद तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की पहल पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का कानून बना और वोडाफोन ग्रुप को फिर से टैक्स चुकाने का नोटिस दिया गया।

राधा सिंह।।

रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून में संशोधन के लिए मोदी सरकार विधेयक लेकर आई है। इस विधेयक के पास होते ही वोडाफोन, केयर्न एनर्जी पीएलसी सहित 17 कंपनियों के साथ सरकार का कानूनी विवाद खत्म हो जाएगा। पहले हुए सौदों पर टैक्स (रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स) कानून में संशोधन के लिए सरकार विधेयक लेकर आई है, जिससे ब्रिटेन के वोडाफोन ग्रुप और केयर्न एनर्जी पीएलसी सहित 17 कंपनियों के साथ कानूनी मुकदमे खत्म हो जाएंगे। यह कानून 28 मई 2012 को यूपीए सरकार ने लागू किया था। इसमें कहा गया था कि सरकार उन मामलों में 50 साल पुराने सौदों में हुए कैपिटल गेन पर टैक्स की मांग कर सकती है, जिनमें मालिकाना हक भले ही विदेश में हुई डील से बदला हो, लेकिन उससे संबंधित संपत्तियां भारत में हों। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर देश में दो सबसे चर्चित मामले वोडाफोन ग्रुप और केयर्न पीएलसी से जुड़े रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत वोडाफोन मामले से हुई थी। 2007 में वोडाफोन ग्रुप ने केमन आइलैंड की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को खरीदा, जिसके पास हॉन्गकॉन्ग के उद्योगपति ली का शिंग के भारतीय टेलिकॉम बिजनेस यानी हचिसन एस्सार का मालिकाना हक था। भारत के टैक्स डिपार्टमेंट ने इस सौदे पर ब्रिटिश कंपनी से 200 करोड़ का टैक्स मांगा। वोडाफोन ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी और केस जीत गई।

इसके बाद तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की पहल पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का कानून बना और वोडाफोन ग्रुप को फिर से टैक्स चुकाने का नोटिस दिया गया। केयर्न एनर्जी पीएलसी को भारत में ऑयल फील्ड में हिस्सेदारी कई इकाइयों में बंटी थी। कंपनी ने 2006 में इनका सबका केयर्न इंडिया लिमिटेड के साथ मर्जर यानी विलय किया। यह केयर्न इंडिया को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की तैयारी थी।

टैक्स डिपार्टमेंट ने दावा किया कि इस मर्जर से केयर्न एनर्जी पीएलसी को लाभ हुआ है और उसने 2015 में कंपनी से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की मांग की। इनमें से एक मामला यूपीए सरकार और दूसरा एनडीए सरकार का है। केयर्न से टैक्स वसूली के लिए सरकार ने उसके शेयर जब्त करके बेच दिए और डिविडेंड से मिली रकम भी रख ली। केयर्न और वोडाफोन दोनों ही मामलों को अंतरराष्ट्रीय अदालतों में ले गईं, जहां फैसला उनके हक में आया। फिर भी भारत सरकार अड़ी रही और उसने अंतरराष्ट्रीय अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील की राह पकड़ी।

केयर्न ने तो इस फैसले के मुताबिक वसूली के लिए भारत सरकार की न्यूयॉर्क से लेकर पैरिस तक की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इससे सरकार की फजीहत हो रही थी। ऐसे में इस विवादित कानून को खत्म करने का फैसला सही है। यूं भी एनडीए सरकार जब सत्ता में आई थी तो उसने यूपीए दौर के 'टैक्स टेररिज्म' को खत्म करने का वादा किया था। लेकिन वैश्विक निवेशकों के बीच छवि बेहतर करने के लिए उसे और भी कदम उठाने होंगे।

उद्दण्डता

अशोक वोहरा।

हनुमान राम के बाणों के प्रहार से निश्चित नारद के बताए मन्त्र का जप करते रहे। वह मन्त्र जैसे हनुमान का कवच बन गया। यह देखकर श्रीराम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान में यह कैसी शक्ति आ गयी है। उनके दण्ड का प्रयास व्यर्थ हो रहा था। विश्वामित्र को लग रहा था कि राम अपने भक्त को बचाने के लिए जानबूझ कर इस तरह बाण चला रहे हैं कि उनको चोट न पहुंचे। अपनी इस असफलता से विचलित होकर राम ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। राम ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया तो हाहाकार मच गया। नारद ने कहा – ऋषिवर विश्वामित्र, हनुमान के अपराध को क्षमा करें। अगर राम का ब्रह्मास्त्र छूट गया तो सिर्फ हनुमान ही नहीं मरेंगे बल्कि सारे लोक में प्रलय मच जाएगा। ब्रह्मास्त्र से निकली ज्वाला देखकर विश्वामित्र भी डर गए।

संपादकीय

आंकस से अलग क्वॉड

भारत की दो मुख्य चिंताएं रही हैं। पहली यह कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले मसले पर उसके साझेदार देश संवेदनशील है या नहीं? इसमें मुझे लगता है कि भारत अपनी बात रखने में सफल रहा। उसने साफ कर दिया है कि वह जल्दबाजी नहीं चाहता और यह भी कि अफगानिस्तान की ओर से उसे टारगेट किया जाए तो मित्र देश उसके साथ खड़े रहें। वह अपने मित्र देशों को लामबंद करने में कामयाब रहा है। दूसरी चिंता भारत के लिए ऑकस डील से क्वॉड को अलग करने की थी। भारत जानना चाह रहा था कि क्वॉड और ऑकस के कामकाज कैसे जमीन पर आकार लेंगे। उस बारे में क्वॉड ने कहा है कि उसे सदस्य देशों को इंडो पैसेफिक में एक विकल्प देना है। चीन के विजन के खिलाफ एक और विकल्प खड़ा करना है। ऐसे में अगर क्वॉड वैक्सीन, टेक्नलॉजी, क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद के मुद्दे पर विकल्प देने में सफल हो जाता है तो चीन कमजोर पड़ जाएगा। कूटनीतिक स्तर पर इस यात्रा के बाद भारत अब इंडो पैसेफिक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, और साथ ही पश्चिमी हिस्से और समान सोच वाले देशों की प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है।

क्वॉड के संयुक्त बयान में भी कहा गया है कि कैसे वह यूरोपियन यूनियन, कोरिया और आसियान के साथ काम कर सकता है। अगर चीन के प्रॉपेगेंडा को बाकी देश या यूरोपियन यूनियन मानने लगे, तो दिक्कत होगी।

भारत को समर्थन

हर्ष वी. पंत।।

तीन दिन की अमेरिका यात्रा के दौरान क्वॉड की मीटिंग में जो तीन–चार बातें हुईं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीन सप्लाई है। ऑकस के नाम से जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में रक्षा समझौता हुआ है, उससे भी क्वॉड ने खुद को यह कहते हुए अलग करने की कोशिश की कि यह कोई सिक्योरिटी प्लैटफॉर्म नहीं है। वैक्सीन सप्लाई की जहां तक बात है तो एक अहम तथ्य यह है कि चीन की वैक्सीन दुनिया भर से वापस की जा रही हैं, यहां तक कि उत्तर कोरिया ने भी उन्हें वापस कर दिया है। इससे एक ऐसी खाई बन रही है जिसे क्वॉड पाट सकता है। लेकिन जब तक क्वॉड की बातें जमीन पर नहीं दिखेंगी, बाकी के देश उससे बहुत उम्मीद नहीं रखेंगे।

भारत ने साफ कहा है कि वह क्वॉड को सिक्योरिटी पार्टनरशिप नहीं मानता और मिलजुल कर काम करना चाहता है। क्वॉड के संयुक्त बयान में भी कहा गया है कि कैसे वह यूरोपियन यूनियन, कोरिया और आसियान के साथ काम कर सकता है। अगर चीन के प्रॉपेगेंडा को बाकी देश या यूरोपियन यूनियन मानने लगे, तो दिक्कत होगी। ऐसे में सवाल है कि क्या क्वॉड इसे काउंटर कर पाएगा? इसे काउंटर करने के लिहाज से क्वॉड में वैक्सीन सप्लाई, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर तो बात हुई ही, तकनीक पर भी बात हुई, जिसमें दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर सेमी कंडक्टर का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव है।

भारत की तरफ से आतंकवाद को लेकर काफी महत्वपूर्ण बात की गई। दोनों देशों के संयुक्त बयान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में पहले के मुकाबले बहुत मजबूत बात रखी गई है और यह भारत की पहल पर हुई है। भारत ने अपने तीनों क्वॉड साझेदारों से यह बात की कि अगर आप चाहते हैं कि हम इंडो पैसिफिक (हिंद प्रशांत) में आपका साथ दें, तो आपको पश्चिमी मोर्चे पर हमारा साथ देना पड़ेगा। इस बात को क्वॉड में समर्थन मिला है। लेकिन इस बारे में भी कुछ ठोस तभी दिखेगा, जब चीजें जमीन पर सामने आएंगी। क्वॉड की तरफ से कोई ऑपरेशनल एक्शन तो नहीं हो सकता। ऑपरेशनली जो होना है, वह द्विपक्षीय स्तर पर होना है। हालांकि मोदी और बाइडन के संयुक्त बयान में इस बात का जिक्र था और कमला हैरिस ने भी आतंकवाद का जिक्र किया।

जब अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी हुई थी, तब भारत में चिंता थी कि अब हम अकेले पड़ गए हैं। अमेरिका कह रहा है कि आप अकेले नहीं पड़े हैं, हम नजर और पाकिस्तान पर दबाव बनाए हुए हैं। यूएन असेंबली में प्रधानमंत्री ने भी साफ किया कि अफगानिस्तान को मान्यता देने की कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, वहां की सरकार समावेशी नहीं है। उनकी इन सारी बातों को माना गया है जिसका नतीजा यह है कि भारत के मित्र देश अभी तक तालिबान के साथ संबंध बनाने की जल्दबाजी में नहीं हैं। यह भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि उसकी अभी तक कोशिश रही है कि तालिबानी सरकार को मान्यता ना मिले। ऐसे में भारत की पॉलिसी कई देशों की पॉलिसी बन चुकी है। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के मानवाधिकार और लोकतंत्र से जुड़ी चिंताओं की भारत में काफी चर्चा हुई। लेकिन भारत और अमेरिका अब मच्योरिटी के उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां आमने–सामने बैठकर अपनी–अपनी चुनौतियों के बारे में बात कर सकते हैं। पहले अक्सर कश्मीर का मुद्दा उठता था, मगर अब अमेरिका में यह मुद्दा उठता ही नहीं।

सुडोकू नवताल- 5347 ***** कठिनतम

				1			6	
					5			
2		3	9			8		
6							5	
			8		3			
	1							4
		7			1	3		9
			2					
	5			6				

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सुडोकू नवताल -5346 का हल

7	6	8	2	1	9	3	4	5
2	1	5	6	3	4	8	7	9
3	4	9	5	7	8	6	1	2
5	7	4	8	6	1	9	2	3
9	2	1	3	4	5	7	8	6
8	3	6	7	9	2	1	5	4
1	5	3	4	8	5	2	9	7
4	9	7	1	2	3	5	6	8
6	8	2	9	5	7	4	3	1

अपना ब्लॉग

समान सोच वाले देशों को साथ लाने की चुनौती

मोहन। अब बात करते हैं कि इस यात्रा से अमेरिका को क्या मिला और भारत को क्या मिला? इंडो पैसिफिक में समान सोच वाले देशों को साथ लाने की चुनौती अमेरिका के सामने है। अब अमेरिका दिखा रहा है कि वह इंडो पैसिफिक में लगा हुआ है। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका पर सवाल उठ रहे हैं कि उसके वादे पर भरोसा कैसे किया जाए? अमेरिका ने क्वॉड मीटिंग करके दिखा दिया कि वह गंभीर है और ऑकस डील करके यह दिखाया कि वह इस इलाके से पीछे नहीं हट रहा है। प्रधानमंत्री ने यूएन असेंबली में लोकतंत्र को बहुत बड़ी जरूरत बताया। अमेरिका ने यह मुद्दा इसलिए भी उठाया कि उसे अपने उन लोगों को जवाब देना होता है, जो इस तरह के वैचारिक मुद्दों को उठाने की बात करते रहे हैं। कमला हैरिस ने इन मुद्दों को उठाकर अपने देश के लोगों को संतुष्ट किया और प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन में भारत को लोकतंत्र की जननी कहकर जवाब भी दे दिया। अमेरिका के सामने फिलहाल जो विश्वसनीयता की समस्या है, उसमें उसे थोड़ा बहुत संदेह का लाभ मिल सकता है।